वर्ष:- 06
अंक:- 64
मुरादाबाद
(Wednesday)
24 June 2026
पृष्ठ:-8
मूल्य:- 3.00 रूपया

दैनिक प्रात: कालीन

क्यूँ न लिखूँ सच

राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र

भारत सरकार से रजिस्टर्ड
RNI No.UPBIL/2021/83001

मुरादाबाद से प्रकाशित

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

फाइलों में अनगिनत नागरिकों की आकांक्षा-जिंदगियां:

युवा IAS अधिकारियों से पीएम मोदी का संवाद, दिया गुरुमंत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं को नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और तकनीक के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटने को कहा। उन्होंने विकसित भारत के लिए परिणाम-आधारित शासन और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2024 बैच के 183 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। ये सभी अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में तैनात हैं। इस दौरान युवा अधिकारियों ने अपने फील्ड प्रशिक्षण और मंत्रालयों के कामकाज के अनुभव साझा किए।प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दो साल के जमीनी अनुभव के बाद वे अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां उनके फैसले करोड़ों नागरिकों का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लोक सेवा की असली परीक्षा ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक स्थितियों को संभालने में है।प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए कहा कि हर प्रशासनिक फाइल के पीछे एक इंसान की उम्मीदें, चिंताएं और जीवन छिपा होता है। अधिकारियों को हर फैसला लेते समय नागरिकों को केंद्र में रखना चाहिए। उन्होंने शासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाने पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने होल-ऑफ-गवर्नमेंट यानी पूरे सरकारी तंत्र के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बड़ी विकास चुनौतियों को अलग-अलग रहकर हल नहीं किया जा सकता। विभागों के बीच बेहतर तालमेल ही सार्थक और स्थायी परिणाम ला सकता है।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक फैसला देश के विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने को आज की प्राथमिकता बताया।पिछले दशक में आए बदलावों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रशासन प्रक्रिया के बजाय परिणामों पर ध्यान देता है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक से सेवाओं में पारदर्शिता आई है और नागरिकों का काम आसान हुआ है।डेटा-आधारित शासन पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह लाखों लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से जांचें कि क्या नीतियां जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं।प्रधानमंत्री ने इस बैच में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं। अंत में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने पद से नहीं, बल्कि अपने काम से मिलने वाले परिणामों से संतुष्ट हों। उन्हें पूरा भरोसा है कि इन युवाओं की ऊर्जा भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के लिए जिम्मेदार अफसरों का केवल सस्पेंशन नहीं, दर्ज हो FIR, आप सांसद ने की मांग

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी और लखनऊ अग्निकांड पर प्रदेश सरकार ठोस कार्रवाई करे। कहा कि चंदा चोरी के साक्ष्य देने के लिए एसआईटी को पत्र और मेल लिखा लेकिन एसआईटी ने साक्ष्य नहीं लिए।आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने आज प्रेसवार्ता में प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड और अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण में हो रहे कथित भ्रष्टाचार व चोरी को लेकर डबल इंजन सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस कंप्यूटर सेंटर की बिल्डिंग में आग लगी, उसे ध्वस्त करने का आदेश 2016 में ही हो चुका था। फिर यह अवैध और जर्जर बिल्डिंग कैसे खड़ी रही? किसके संरक्षण में इसे चलाया जा रहा था, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।सांसद ने फायर डिपार्टमेंट की बदहाली पर कहा कि जब लोग दमकल विभाग को फोन कर रहे थे, तो समय पर कोई गाड़ी नहीं पहुंची। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर अग्निकांड के बाद केवल जांच का नाटक होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि- 1. उत्तर प्रदेश के पूरे फायर डिपार्टमेंट की समीक्षा की जाए, विभाग का बजट बढ़ाया जाए और उन्हें आधुनिक उपकरण, पाइप व गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएं।

जटिल चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका अहम; भारत ने US-ईरान समझौते का किया स्वागत

ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अजीत डोभाल ने अमेरिका-ईरान समझौते का स्वागत करते हुए इसे ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए सकारात्मक बताया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक्स को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद अहम बताया और आतंकवाद व साइबर खतरों के खिलाफ साझा प्रयासों पर जोर दिया।भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (हृ) अजीत डोभाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौते (MoU) का स्वागत किया और इसे दुनिया के लिए एक सकारात्मक कदम बताया।
अमेरिका-ईरान समझौते का स्वागत- अजीत डोभाल ने कहा कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति को लेकर सावधानी के साथ सकारात्मक उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह समझौता सही तरीके से काम करेगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा को बहुत मदद मिलेगी।
उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के खुलने को एक बड़ी राहत बताया। डोभाल के अनुसार, इस समुद्री रास्ते के खुलने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। इससे खाद और रसायनों जैसी जरूरी चीजों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समुद्री आवाजाही की आजादी से क्षेत्र के देशों की आर्थिक समृद्धि में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले इस शांति वार्ता का समर्थन किया था।
उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने दुनिया भर में आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि इस समझौते से क्षेत्र में शांति बहाल होगी और व्यापार सुरक्षित होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस बातचीत को बहुत सफल बताया है।
ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और जिम्मेदारी- बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स (BRICS) केवल देशों का समूह नहीं है। ये दुनिया की लगभग आधी आबादी का एक साझा घर है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया अस्थिरता और तनाव का सामना कर रही है, तब ब्रिक्स की भूमिका बहुत खास हो जाती है।
आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों में 3.9 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत है। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान देता है। डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सबकी आवाज सुनी जाए और विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके।
सुरक्षा चुनौतियां और आतंकवाद पर चिंता- एनएसए डोभाल ने मौजूदा वैश्विक हालात को काफी मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय सैन्य संघर्षों, आर्थिक दबाव और बदलती तकनीक की चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने चिंता जताई कि पुरानी संस्थाएं और नियम इन झगड़ों को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।उन्होंने गैर-पारंपरिक खतरों को लेकर भी आगाह किया। डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के नए और छिपे हुए रूप, साइबर हमले और खतरनाक तकनीक अब देशों की सीमाओं को पार कर चुके हैं। इनसे निपटने के लिए पुराने तरीके अब काफी नहीं हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे इन खतरों के प्रति सतर्क रहें और मिलकर इनका मुकाबला करें। बैठक में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और सूचना तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। भारत इस समय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें सदस्य देशों के शीर्ष अधिकारी वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। डोभाल ने सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

तृणमूल कांग्रेस दो फाड़: ममता बनर्जी ने खुद को TMC चीफ बताया, EC को सौंपी सूची;बागी गुट का अध्यक्ष अलग

पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवा चुकी तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक और बड़ा विद्रोह सामने आया है। पार्टी के कम से कम 58 विधायकों ने पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है। दोनों गुटों ने अलग-अलग अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस दो फाड़ होने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास कितनी ताकत बची है? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विपक्ष को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के पास जो दस्तावेज / सूची जमा कराई है, इसमें उन्होंने खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया है। दूसरी तरफ ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में अपनी राहें अलग करने वाले बागी गुट ने अलग अध्यक्ष की घोषणा की है। ऐसे में अब सबसे रोचक सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? दोनों धड़ों के अपने-अपने दावे, किसने क्या कहा? - दरअसल, बागी विधायकों ने ममता बनर्जी की जगह अरूप रॉय को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पार्टी पदाधिकारियों की एक सूची सौंपी। इस सूची में उन्होंने खुद को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष दिखाया है।इससे पहले सोमवार को, विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने अरूप रॉय को नया पार्टी अध्यक्ष घोषित किया। उन्होंने ममता बनर्जी से संरक्षक की भूमिका निभाने का आग्रह किया। ममता बनर्जी द्वारा 20 जून, शनिवार तक की स्थिति के अनुसार पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की सूची साझा की गई। इस सूची में ममता बनर्जी अध्यक्ष, सुब्रत बख्शी उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। डेरेक ओ%ब्रायन और डोला सेना संयुक्त सचिव जबकि सुभाशीष चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति की जानकारी दी।ऋतब्रत बनर्जी ने अरूप रॉय को नया तृणमूल कांग्रेस प्रमुख घोषित किया था। उन्होंने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का भी एलान किया। ऋतब्रत बनर्जी ने बताया कि अरूप रॉय को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति में फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन और ऋतब्रत बनर्जी सहित 29 अन्य सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे ममता बनर्जी को संरक्षक के रूप में देखना चाहते हैं।तृणमूल कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने कई वरिष्ठ नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, अरूप रॉय, जावेद खान, रथिन घोष और सबीना यास्मीन शामिल हैं। उन पर जानबूझकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पार्टी फंड, अध्यक्ष का पद और चुनाव चिह्न अब दोनों गुटों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे बन गए हैं। बागी गुट ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की जगह ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाया है।

कांग्रेस की पीएम मोदी को सलाह: ट्रंप को खुश करना बंद करें, देश हित के खिलाफ व्यापार समझौते पर न करें हस्ताक्षर

कांग्रेस ने पीएम मोदी को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता न करने की सलाह दी है। जयराम रमेश ने कहा कि यह समझौता भारत के खिलाफ है। उन्होंने मोदी से ट्रंप को खुश करना बंद करना और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत के दौरे पर आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अच्छे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करना चाहिए। पार्टी के मुताबिक, भारत को किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं है जो देश के हितों के खिलाफ हो।इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को मलेशिया से प्रेरणा लेनी चाहिए। मलेशिया ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के साथ अपना व्यापार समझौता रद्द कर दिया था।रमेश ने बताया कि छह फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने व्यापार पर एक साझा बयान जारी किया था। उस समय राहुल गांधी ने संसद में चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। रमेश का आरोप है कि उसी दबाव में यह बयान आया था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैक्स 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का वादा किया था। बदले में भारत ने अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैक्स खत्म करने या बहुत कम करने का वादा किया। साथ ही भारत ने पांच साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने की बात कही थी।लेकिन 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैक्स रणनीति को अवैध घोषित कर दिया। इससे भारत को मिलने वाली छूट रातों-रात खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का अस्थायी टैक्स लगा दिया। इसकी कानूनी समय सीमा 24 जुलाई 2026 को खत्म हो रही है। इसके बाद क्या होगा, इसे लेकर काफी अनिश्चितता है।जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका अब भारत सहित करीब 60 देशों की जांच कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ये देश व्यापार में गलत तरीके अपना रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि अमेरिका इस जांच का इस्तेमाल भारत को डराने के लिए कर रहा है। वह चाहता है कि भारत छह फरवरी वाले समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत कर दे।रमेश ने इस समझौते को भारत के लिए घाटे का सौदा बताया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत अपनी तरफ से आयात तीन गुना बढ़ाने का वादा कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई ठोस वादा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों को टैक्स बढ़ाने की धमकी दे सकता है, तो भारत के साथ समझौते के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? अंत में रमेश ने कहा कि पीएम मोदी को ट्रंप को खुश करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। ट्रंप ने %ऑपरेशन सिंदूर% को 100 से ज्यादा बार रोकने का दावा किया है, लेकिन मोदी ने अभी तक इस दावे को चुनौती नहीं दी है।

संपादकीय Editorial

If India is attacked, we will help.

Indian Prime Minister Modi and US President Trump met after nearly 16 months. While they shook hands, they didn't embrace warmly. Why? During this momentous meeting, many knots must have been unraveled, misconceptions must have been shattered, perceptions must have changed, and many ices must have melted. Consequently, President Trump expressed condolences for the killing of three Indian sailors in the Gulf of Oman and assured the safety of all sailors in the future. This bilateral meeting took place on the sidelines of the G-7 summit in France. President Trump surprised the world by making the first statement: "If anyone attacks this man (referring to Prime Minister Modi), we will help India. As long as Prime Minister Modi is in power, the US will stand with India in every attack." President Trump also made it clear that if India has a new leader, he (Trump) will have to think again. The US President's comments came when asked about defense cooperation with India. India and the US are undoubtedly strategic partners. They have agreements on defense, security, and safety. These agreements are both emotional and documented. The most significant example is the Quad, which includes India and the US, as well as Japan and Australia. The Indian Ocean and Pacific Ocean regions are extremely important and sensitive for these countries. Approximately 35% of trade flows through the Indian Ocean. China is also present there, and sometimes even shows arrogance. Therefore, for America's presence and active presence in this region, and to counter China's aggression, the US needs India. There is no other option.

President Trump's statement likely stems from this very context and sensitivity. Furthermore, during Operation Sindoor in May 2025, China and Turkey provided military assistance to Pakistan, yet the Indian Air Force reduced Pakistani airbases and aircraft to rubble. However, President Trump has now publicly stated that the United States will assist India in the event of any attack. This clearly signals a historic shift in diplomatic dynamics, as India, formerly a supporter of the Soviet Union, remains a close friend of Russia, but is also a declared strategic partner of the United States. Prime Minister Modi has clearly told President Trump that the partnership should be equal and respectful. Any relationship thrives on trust. India-US relations have experienced ups and downs over the past 16 months. The US President has labeled India a "dead economy," compared India to hell, and even imposed a 50% tariff on India. These statements may have been made in a fit of rage, but the reality is that the two countries are complementary. Regarding defense cooperation, India today purchases 40% of its weapons from Russia, approximately 29% from France, and 15-16% from Israel. The United States is almost absent from this list, despite being the world's largest supplier of arms, accounting for approximately 42%. This reality likely troubles President Trump! Perhaps this is why Trump has allowed India to purchase crude oil from Russia. The US embargo ended on Wednesday. Nevertheless, President Trump expressed hope for a "trade agreement" with India and described his talks with Prime Minister Modi as "fruitful." He anticipated trade with India exceeding $19 trillion. India exports approximately 30% of its electronic machinery and equipment, approximately 10% of its pharmaceuticals, and 2% of its nuclear reactors to the United States. This key meeting, however, comes just days after the signing of a US-Iran peace agreement on Friday. President Trump believes India's contribution to the world order is invaluable. He repeatedly called Prime Minister Modi a "true friend" and has also promised to visit India soon.

The Results of Making the Right Choices

Prime Minister Modi has positively transformed India through his policies and leadership. His effective leadership during the COVID crisis. Balanced economic policies have led to India's strong growth. Self-reliance and security through indigenous vaccine production. A politician is judged by his policies and leadership, and his greatest test comes in times of crisis. Prime Minister Modi is a leader who meets all these criteria. After setting new benchmarks for progress for the state as Chief Minister of Gujarat, he has positively transformed India through decisive decisions as Prime Minister for the past 12 years. I am fortunate to have had the opportunity to work with him. He broadened financial inclusion by connecting the underprivileged to banking services through Jan Dhan bank accounts and launched an online payment revolution through UPI that overwhelmed not only the country but the world. Even during a COVID pandemic that brought the entire world to its knees, he handled the country with remarkable leadership. During this period, tough decisions like the national lockdown were certainly taken, but they saved the country from catastrophe. Institutions like Johns Hopkins and Princeton predicted that India would see an average of ten thousand deaths daily during the peak of COVID. PM Modi's resolve to endure political pain to prevent a humanitarian disaster was a prime example of his exemplary leadership. Recall the devastating COVID period when patients in developed countries like Italy and Spain were being treated outside hospitals. Even then, despite a relatively weak health infrastructure, India was far more successful in handling the crisis. During this time, India dared to develop indigenous vaccines because it had to accept the arbitrary conditions of multinational companies to purchase them. Had India not developed its own vaccine, no other country would have provided vaccines, and millions of people would have remained deprived indefinitely. The indigenous vaccine proved to be not only a vaccine against COVID, but also an effective vaccine for the economy, significantly helping to quickly restore normalcy and restore development activities. A commendable aspect of PM Modi's leadership is his macroeconomic policy. While advanced economies focused solely on demand-side stimulus, India chose a balanced combination of supply-side and demand-side measures, with a strong emphasis on infrastructure. The wisdom of this choice is clearly visible in the post-COVID economic data. Advanced economies faced inflation rates two to four times higher than their historical averages, while India's inflation rate remained below its historical and traditional averages. India emerged from COVID with robust economic growth of around 8% and strong economic stability despite COVID. A comparison of this scenario with the global financial crisis of 2008-09 further clarifies the picture. The demand stimulus bets of advanced economies led to double-digit monthly inflation rates for 18 months, even when the global financial crisis was not a supply-side shock, unlike the COVID shock. Had India imitated advanced economies during COVID, we would have faced inflation rates above 20% for several years. Modi's determination to make the right choice saved India from that predicament. After the 2019 budget, when I was called to 7, Lok Kalyan Marg to present on the ideas contained in the Economic Survey, I assumed other ministers and senior officials would be present. Upon arriving, I was surprised to find only the Prime Minister alone. Throughout my time in government service, I've never seen his approach to nuance change. Of all the high-level positions I've worked at, I found the Prime Minister to be the most approachable. He puts others at such a level of comfort that it's incredibly easy to express his views. In our very first meeting, he encouraged me with a remark like, "How do you speak Hindi so well?" On the day of the 2019 budget, when he introduced me to the Cabinet, he said, "Don't go by your name; you speak fluent Hindi." Such a warm, cordial demeanor from any boss will inspire those working with him to strive for greater excellence. It was his ease that gave me the courage to tell him at the end of my tenure: "Sir, if you don't implement economic reforms, the country will miss the bus to progress." I don't come from a family or background of IAS, IPS, or IRS officers. He appointed me solely based on my talent, rather than any recommendation or background, which shows how much ethics and merit matter to him. It was a sign that he is committed to building an India where talent and hard work, not family, determine a person's success. I first saw him at the NITI Aayog budget meeting in January 2018. I was sitting in the last row and was given three minutes to speak on banking reform. After speaking, I looked out the window, lost in thought. As I turned to where he was sitting, I found him waiting for my gaze. When our eyes met, he nodded approvingly and smiled. I immediately texted my wife and brother: 'The PM has agreed!' Little did I know that this was the beginning of a privilege for which I would be grateful for the rest of my life, or the opportunity to work closely with a leader who would have an indelible mark on India's history.

The three-language formula is in the best interest of students.

According to a study, only one percent of urban students are studying foreign languages ??as a third language. The three-language formula will be implemented in grades six and nine from 2026-27. It will make teaching at least two Indian languages ??mandatory. This will strengthen students' linguistic development and national unity. Language is not merely a medium of communication; it also has a sociology and economics. Especially when the perspective of language is in the context of education, language transcends its sociology and economics and becomes integrated into the process of nation-building. The recent announcement of a plan to implement the three-language formula in CBSE schools across the country should be seen in this context. It is a different matter that this issue has sparked controversy across the country. It is satisfying that the Supreme Court did not put a stay on the government's decision. The Central Board of Secondary Education (CBSE), India's premier school education board, recently decided to implement the three-language formula from the sixth and ninth grades starting the 2026-2027 academic year. The three-language formula is recommended in the National Education Policy. According to this, three languages ??will be taught at the school level, including at least two Indian languages. Previously, the three-language formula was adopted in slightly different forms in the NEP 1968 and NEP 1986. All but a few states implemented the three-language formula, but unfortunately, the CBSE only partially accepted it. While the three-language formula was implemented in CBSE schools from sixth to eighth grade, foreign languages ??were also allowed as the third language. In ninth and tenth grades, the CBSE adopted only a two-language policy. Even within that, the school could choose non-Indian languages ??if it so desired. This resulted in the neglect of Indian languages ??in expensive public schools. These CBSE policies created many inconsistencies. Language learning between CBSE and state board students was inconsistent. The current plan aims to establish equality and linguistic uniformity in school education across the country. Secondly, limiting children to foreign languages ??in the ninth and tenth grades, when their personalities begin to take shape, alienates them from their Indian culture. Language also instills socio-cultural values. Today, Indian values ??like sacrifice, service, tolerance, collectivism, family spirit, and respect for elders are disappearing among children. The three-language formula of the NEP 2020 will preserve these diminishing Indian socio-cultural values. CBSE students will also benefit from the power of multilingualism. Psycho-linguistic research shows that children have an innate and unlimited capacity to learn multiple languages. Knowledge of more than one Indian language will enrich children's understanding of Indian geography and culture. This will strengthen the sense of national unity and weaken divisive linguistic politics. Language also has an economics. The study and teaching of Indian languages ??will boost the publishing industry and employment opportunities. Furthermore, it will facilitate social interaction, employment, business, education, and tourism across the country. The information being spread by opponents is baseless and misleading. One reason for this opposition is the colonial-era "Macaulay mentality" of the English-educated elite. According to a study, only one percent of urban students are studying foreign languages ??as a third language. These elite parents are opposing the mandatory study of Indian languages. These people are citing the shortage of language teachers, lack of textbooks, additional burden and stress on students, and inconvenience to students already studying foreign languages. It should be noted that CBSE/NCERT has almost prepared textbooks in all 22 scheduled languages ??for grade six. The three-language policy will be implemented in grade nine from July 1, 2026. Textbooks for 19 scheduled languages ??will be made available soon. This year, NCERT textbooks will be available for other Indian languages. From hiring new guest lecturers to collaborating with other schools through online teaching, teaching is not impossible. Calling the study of just one more Indian language an additional burden lacks understanding. Three languages ??are already being taught in various states. For the convenience of students already studying foreign languages, the curriculum for the third language will be kept light. There is also the flexibility for the third language, as there will be no board exam in the tenth grade. Furthermore, students wishing to learn a foreign language other than English will also have the opportunity. While major reforms naturally face some initial challenges, there is no doubt that properly implementing the three-language policy is in the best interest of both the country and children.

सावधान! यूपी के इन 6 नेशनल हाईवे पर अब 40 से ऊपर नहीं चलेगी गाड़ी, नया नियम लागू

मुरादाबाद में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति ने प्रमुख हाईवे और राज्य मार्गों पर नई गति सीमा लागू की है। अब भारी वाहन 40 किमी/घंटा और आबादी वाले क्षेत्रों में 30 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगे, जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी/घंटा तय की गई है।जिले की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच जिला सड़क सुरक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया है।

अब जिले के प्रमुख हाईवे और राज्य मार्गों पर दौड़ने वाले ट्रक, डंपर, रोडवेज बस और अन्य भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से नहीं चल सकेंगे। आबादी वाले क्षेत्रों में इनकी अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है।

दूसरी ओर बाइक, कार और आठ से 12 सीट वाले हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।यह निर्णय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-112 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-178 के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डा. आंजनेय सिंह ने अधिसूचना जारी कर नई गति सीमा लागू करने के आदेश दिए हैं।मार्ग का नाम दोपहिया कार / हल्के चार पहिया 8 - 12 सीट वाले वाहनभारी वाहन- दलपतपुर-अलीगंज मार्ग 60 60 60 4 0 (आबादी क्षेत्र में 30) स्टेट हाईवे-149 60 60 60 4 0 (आबादी क्षेत्र में 30) मुरादाबाद-हरिद्वार/देहरादून मार्ग 60 60 60 40 (आबादी क्षेत्र में 30) अलीगढ़-मुरादाबाद मार्ग (एनएच-509) 60 60 60 4 0 (आबादी क्षेत्र में 30) मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर मार्ग (एसएच-148) 60 60 60 नई व्यवस्था के तहत दलपतपुर-अलीगंज मार्ग (एमडीआर-174डब्ल्यू), स्टेट हाईवे-149, मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग, अलीगढ़-मुरादाबाद

(एनएच-509), मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर मार्ग, मुरादाबाद-टांडा-दढ़ियाल मार्ग और वहसुमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग पर यह नियम लागू रहेगा।मार्ग का नाम दोपहिया कार / हल्के चार पहिया 8-12 सीट वाले वाहन भारी वाहन मुरादाबाद-टांडा-दढ़ियाल मार्ग 60 60 60 40 (आबादी क्षेत्र में 30) वहसुमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग 60 60 60 4 0 (आबादी क्षेत्र में 30) नगर निकाय सीमा से बाहर इन सभी मार्गों पर छोटे वाहनों की गति 60 और भारी वाहनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सबसे अहम बदलाव आबादी वाले हिस्सों में किया गया है। गांव, बाजार और घनी आबादी से गुजरने वाले क्षेत्रों में ट्रक, डंपर और अन्य भारी वाहनों को अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही गुजरना होगा। प्रशासन का मानना है कि सबसे अधिक गंभीर हादसे ऐसे ही क्षेत्रों में होते हैं, जहां तेज रफ्तार भारी वाहन पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों के लिए खतरा बनते हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सड़क स्वामी विभागों को सभी मार्गों पर भारतीय सड़क कांग्रेस (आइआरसी) के मानकों के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने होंगे, ताकि रात में भी चालक आसानी से गति सीमा देख सकें। मुरादाबाद गति सीमा- मुख्य नियम और छूट -वाहन का प्रकार / श्रेणी अधिकतम गति सीमा (किमी/घंटा) विशेष परिस्थिति / छूट दोपहिया (क्ष्ड्ढद्र) 60 सामान्य हाईवे और मुख्य मार्गों पर कार और हल्के चार पहिया 60 सामान्य हाईवे और मुख्य मार्गों पर 8 से 12 सीट वाले वाहन 60 सामान्य हाईवे और मुख्य मार्गों पर भारी वाहन (ट्रक, डंपर, रोडवेज बस आदि) 40 नगर निकाय सीमा से बाहर, मुख्य मार्गों पर आबादी वाले क्षेत्र (गांव, बाजार, घनी आबादी) 30 केवल भारी वाहनों (ट्रक-डंपर) के लिए अनिवार्य आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाएं लागू नहीं (छूट) एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और आपदा प्रबंधन वाहन- मार्ग के दोनों सिरों के अलावा बीच-बीच में भी संकेतक लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस पहले वाहन चालकों को नई गति सीमा के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए प्रमुख मार्गों पर बैनर और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर ओवरस्पीड वाहनों की जांच होगी और निर्धारित सीमा से अधिक गति मिलने पर चालान व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी हालांकि कुछ आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में लगे सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के वाहन इस गति प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। एसपी यातायात सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि जिले के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की गति सीमा घटाई गई है। पहले वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा, इसके बाद ओवरस्पीड के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुरादाबाद में ज्ञापन देने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने संभाला

मुरादाबाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट हुई।मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर बैठे। धर्मांतरण के आरोप पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गए थे। एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिस ने स्थिति को संभाला।जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के बाद मारपीट होने लगी। इससे एसएसपी आफिस के बाहर हंगामा हो गया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली। मामले का शिकायती पत्र पुलिस को दिया गया है। बजरंगदल के कार्यकर्ताओं को आरोप है कि मझोला क्षेत्र में मतांतरण कराया जा रहा है। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला अधिकारी को सोमवार दोपहर ज्ञापन सौंपने गए थे। जैसे ही कार्यकर्ता एसएसपी आफिस के पास पहुंचे तो हिमगिरी निवासी बजरंग दल के कार्यकर्ता सुधांशु का दूसरे कार्यकर्ता तनिष्क से विवाद हो गया। गाली गलौज हुई तो कार्यकर्ता दो गुट में बट गए। दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। जमकर हंगामा हुआ।सूचना पर सिविल लाइंस पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर शांत किया। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

दहेजलोभियों की पिटाई से महिला की मौत, पति सहित तीन पर आरोप

केमरी थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों ने महिला की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। महिला के मायके वालों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया है। मृतका के कोई बच्चा नहीं है। तहसील मिलक के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी मृतका के भाई मोहम्मद यासीन ने थाना केमरी में तहरीर दीञ इसमें कहा कि उसकी बहन अफसाना की शादी 9 वर्ष पूर्व सलीम पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम कुईया के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी और काफी दान दहेज दिया था। लेकिन शादी के एक माह बाद से सलीम अपनी पत्नी अफसाना को कम दहेज लाने का ताना देने लगा था। जब मामला बहुत बढ़ गया इसके बाद अफसाना ने अपने मायके वालों को पूरी बात बताई। इसके बाद कई बार पंचायतें हुईं और सलीम राजीनामा करते हुए अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। अपने घर ले जाने के बाद सलीम एक बार फिर अफसाना के साथ मारपीट करने लगा। तहरीर में कहा गया है कि सलीम के साथ उसके पिता मोहम्मद अली और उसकी मां जाफरीन मिलकर पीटते थे। 16 जून 2026 को सलीम ने अफसाना के भाई आरिफ को फोन करके बताया कि अफसाना ने दहेज की मांग पूरी नहीं की तो हमने इसको इतना मारा है कि यह मरने की स्थिति में आ गई है। इसे उठाकर ले जाओ। आरिफ ने घर में बताया तब अफसाना की मां शाह जहां कुईया गांव पहुंच गईं। आरोप है कि अफसाना के ससुर, पति, सास देखकर आग बबूला हो गए। कहा कि अफसाना को जल्दी ले जाओ वरना आपका भी बुरा हाल करेंगे। इसके बाद शाहजहां अफसाना को अपने घर ले आईं और उसका इलाज कराने लगे। 21 जून को अफसाना की हालत अंदरूनी चोटों के कारण बिगड़ने लगी।

मौत की सुरंग बने कोचिंग सेंटर! न फायर एनओसी, न निकलने का रास्ता; मुरादाबाद में बड़ा खुलासा

लखनऊ अग्निकांड के बाद मुरादाबाद में कोचिंग सेंटरों की पड़ताल में सुरक्षा खामियां सामने आईं। अग्निशमन यंत्रों की कमी, तारों का जाल और संकरे रास्ते छात्रों के लिए खतरा हैं।लखनऊ अग्निकांड के बाद मुरादाबाद में पड़ताल में सामने आई खामियां आग लगने की स्थिति में छात्रों की जान पर बन सकती है आफतलखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का दावा करने वाले कई संस्थानों में आग से बचाव की मूलभूत व्यवस्थाएं तक नहीं हैं। कहीं अग्निशमन यंत्र नदारद मिले तो कहीं बिजली के तारों का खतरनाक जाल लटका मिला। कई संस्थानों में छात्रों के आने-जाने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता है, जो किसी भी आपात स्थिति में मौत की सुरंग साबित हो सकता है।शहर के हिमगिरि क्षेत्र में एसडीएम स्कूल के निकट संचालित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में तीन मंजिलों पर कोचिंग और लाइब्रेरी संचालित है। यहां प्रतिदिन करीब 160 विद्यार्थी आते हैं, लेकिन पूरी इमारत में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। भवन तक पहुंचने के लिए संकरी गली और बाहर निकलने के लिए सीमित रास्ता है।राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनुसार कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा नियम- श्रेणी (Category) सुरक्षा नियम और मानक (Safety Rules & Standards) निकास एवं सीढ़ियां (E&it & Stairs) प्रत्येक बड़े क्लासरूम या हॉल में कम से कम दो निकास द्वार होने चाहिए। आपातकालीन सीढ़ियां खुली, अवरोध रहित और कम से कम 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। निकास मार्गों पर स्पष्ट और चमकदार 'EXIT' (निकास) संकेतक लगाए जाएं। आपातकालीन स्थिति में निकासी योजना

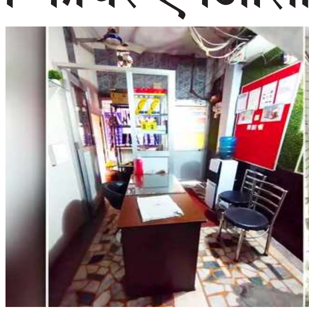

(Evacuation Plan) भवन में साफ दिखाई देने वाली जगह पर प्रदर्शित हो। फायर फाइटिंग सिस्टम (Fire Fighting) प्रत्येक मंजिल और कक्ष के बाहर पर्याप्त क्षमता वाले अग्निशामक यंत्र (Fire E&tinguishers) लगाए जाएं। भवन में स्मोक डिटेक्टर एवं फायर अलार्म सिस्टम स्थापित होना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में स्वत: सक्रिय होने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुरक्षा (Electrical Safety) भवन में केवल फ्लेम-रेटार्डेंट (आग प्रतिरोधी) एवं मानक के अनुरूप वायरिंग हो। खुले, लटकते या अव्यवस्थित बिजली के तार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। विद्युत पैनल और मीटर सुरक्षित स्थान पर स्थापित हों तथा उनकी नियमित जांच कराई जाए। भवन संरचना व क्षमता (Building & Capacity) बिना पर्याप्त वेंटिलेशन और निकास व्यवस्था के बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी संचालित नहीं की जा सकती। भवन की तय क्षमता के अनुरूप ही छात्रों की संख्या (Overcrowding रोकने के लिए) सुनिश्चित की जाए। कानूनी कागजात व ट्रेनिंग (NOC & Training)

संस्थान के पास अग्निशमन विभाग से जारी वैध फायर एनओसी (Fire NOC) होना अनिवार्य है। इस फायर एनओसी का समय-समय पर नवीनीकरण (Renewal) कराया जाए। छात्रों एवं स्टाफ के लिए प्रत्येक छह माह में मॉक ड्रिल आयोजित की जाए ताकि आपातकाल से निपटा जा सके। हादसे की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है। कांठ रोड पर पीएसी स्थित एक बड़े कोचिंग संस्थान के बाहर विद्युत मीटरों के पास तारों का जाल लटका मिला। यहां प्रतिदिन करीब 1300 विद्यार्थी भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना लेकर तैयारी के लिए आते हैं। अधिक लोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यह तार बड़ा हादसा पैदा कर सकते हैं। संस्थान दूसरे और तीसरे तल पर संचालित है तथा छात्रों के आवागमन के लिए मुख्य रूप से एक ही सीढ़ी का सहारा है। नयागांव क्षेत्र में अनिल परचून दुकान के पास संचालित एक कोचिंग संस्थान में भी अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। वहीं हिमगिरि तिराहा स्थित एक लाइब्रेरी में प्रवेश और निकास के लिए बनी संकरी सीढ़ियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। नवीन नगर स्थित एक स्टडी प्वाइंट में भी विद्यार्थियों के लिए केवल एक तंग प्रवेश द्वार है। बड़ी संख्या में छात्रों के एक साथ बाहर निकलने की स्थिति में यहां भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। फायर ब्रिगेड की पहुंच भी चुनौती- नयागांव और हिमगिरि क्षेत्र के कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे स्थानों पर संचालित हैं जहां तक संकरी गलियों के कारण अग्निशमन विभाग के बड़े वाहन आसानी से नहीं पहुंच सकते। ऐसे में शुरुआती कुछ मिनटों में हालात बेकाबू होने का खतरा बढ़ जाता है। पड़ताल में सामने आए बड़े खतरे कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। बिजली के खुले और उलझे तार हादसे को न्योता दे रहे हैं। अधिकांश भवनों में वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं। कई कोचिंग दूसरे और तीसरे तल पर संचालित। संकरी सीढ़ियां और तंग गलियां बचाव कार्य में बाधा बन सकती हैं। 5 से 10 मिनट लगते हैं एक छात्र को सड़ियों से उतरने में।

संक्षिप्त समाचार

आठ साल अंधेरे में गुजारे, मुरादाबाद में 16 साल बाद मिला इंसाफ; बिजली विभाग की मनमानी पर जीत

संतोष कुमार शर्मा को बिजली विभाग के खिलाफ 16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुरादाबाद कोर्ट से इंसाफ मिला। विभाग ने 2008 में कनेक्शन काटा और 2010 में सरकारी काम में बाधा डालने का झूठा मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अब वे बरी हुए हैं।संतोष शर्मा को 16 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला। बिजली विभाग ने 2008 में कनेक्शन काटा था। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप से बरी हुए।बिजली विभाग की मनमानी कार्रवाई से घर की रोशनी छिन गई। परिवार आठ साल तक अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर रहा। विरोध करने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा भी झेलना पड़ा। हालांकि, सुरेश ने तंत्र के आगे घुटने टेकने की जगह इंसाफ के लिए जंग लड़ी। करीब 16 वर्षों तक लड़ाई के बाद आखिरकार संतोष कुमार शर्मा को मुरादाबाद के एसीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया। निर्यात फर्म में कर्मचारी संतोष कुमार शर्मा के अनुसार वर्ष 2008 में बिजली विभाग ने बिना स्पष्ट कारण उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने और विभिन्न जनसुनवाई मंचों पर अपनी बात रखने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। संतोष का आरोप है कि लगातार शिकायतों से नाराज अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भूमिका तैयार की।इसी क्रम में 28 अक्टूबर 2010 को बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिल का हवाला देते हुए उनके घर का मीटर उतारने पहुंचे। विभाग ने अक्टूबर 2010 में सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में दर्ज कराई थी प्राथमिकी विभाग ने आरोप लगाया कि संतोष कुमार शर्मा और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने कर्मचारियों को सरकारी कार्य करने से रोका और बाधा पहुंचाई। इस आधार पर मझोला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे के बाद संतोष को तीन दिन जेल में भी रहना पड़ा और बाद में उन्हें जमानत मिली। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने और बाद में सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाने के बाद वर्ष 2015 में उनकी पत्नी के नाम नया बिजली कनेक्शन जारी किया गया।मुरादाबाद की एसीजेएम कोर्ट में साक्ष्य साबित न होने और गवाह मुकरने से बरी किये गए संतोष- उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। बहस में विभाग का पक्ष कमजोर पड़ गया। वादी व जेई सुमित कुमार ने स्वीकार किया कि मीटर उतारने के लिए उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं था और वे केवल मौखिक निर्देश पर पहुंचे थे। जूनियर मीटर रीडर (जेएमटी) विजय कुमार गुप्ता ने अदालत में कहा कि वह घटनास्थल पर गया ही नहीं, बल्कि इस तरह की कार्रवाई करने से रोका भी।सरकारी कर्मचारी विधिपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-छह की अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि सरकारी कर्मचारी विधिपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे या अभियुक्त ने उन पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग किया था। इस प्रकरण का दूसरा पहलू यह भी है कि संतोष शर्मा को अप्रैल 2024 में दोषमुक्त हो जाने की जानकारी अदालत के फैसले की छह मई 2026 को प्राप्त सत्यापित प्रति से मिली।अब संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जंग संतोष कुमार शर्मा ने इसे केवल अपनी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की मनमानी के खिलाफ संघर्ष करने वाले आम नागरिकों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अब वह जेई सुमित कुमार, एसडीओ योगेश कुमार (अब सेवानिवृत्त), व विवेचक धर्म सिंह, चार्जशीट लगाने वाले एसआइ ओमप्रकाश सिंह, गिरफ्तार करने वाले दारोगा अजय सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेंगे। क्योंकि इन्हीं की वजह से उन्हें व परिवार को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ीं।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए
9027776991
knlslive@gmail.com

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा
मो. 9027776991
RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

ज्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

शिया जामा मस्जिद नय्यर खातून, आजाद नगर में छठी मुहर्रम की मजलिस आयोजित

क्यूँ न लिखूँ सच /सिकंदर राजा/ मुरादाबाद। मुहर्रम-उल-हराम 1448 हिजरी के सिलसिले में छठी मुहर्रम की मजलिस शिया जामा मस्जिद नय्यर खातून, आजाद नगर में अकीदत, एहतराम और धार्मिक वातावरण के बीच आयोजित की गई। मजलिस को खिताब करते हुए जनाब काशिफ साहब ने वाक़ेआ-ए-कर्बला के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) तथा उनके वफ़ादार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कर्बला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत, सत्य, न्याय, सब्र और कुर्बानी का ऐसा पैग़ाम है जो क़यामत तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। इमाम हुसैन (अ.स.) ने अपने अहल-ए-बैत और वफ़ादार साथियों के साथ मिलकर इस्लाम की असल रूह और इंसानी मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कर्बला से यह सबक लेना चाहिए कि जब भी दीन, इंसाफ और हक़ की हिफाज़त का वक्त आए, तो किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए।

काशिफ साहब ने कहा कि इमाम हुसैन (अ.स.) का पैग़ाम हमें अत्याचार, झूठ और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। कर्बला का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, जो सत्य और न्याय की राह पर चलने का संदेश देता है।

मजलिस में मौजूद अकीदतमंदों ने बड़े अदब और एहतराम के साथ बयान को सुना तथा शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। मजलिस के दौरान ग़म-ए-हुसैन (अ.स.) में नौहाख़्वानी और मातमदारी का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे पूरा माहौल अज़ादारी के रंग में रंगा नजर आया।

इस अवसर पर मौलाना शकील साहब, मौलाना शान-ए-रज़ा साहब, शबाब भाई, एडवोकेट दिलावर साहब, जाकिर अली, जमीर बकरी साहब, राजू बकरी, जावेद मंसूरी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।

मजलिस के अंत में मुल्क में अमन-ओ-अमान, आपसी भाईचारे, इंसानियत की भलाई तथा शोहदाए कर्बला के सदके में पूरी उम्मत की सलामती के लिए विशेष दुआ कराई गई। छठी मुहर्रम की यह मजलिस इमाम हुसैन (अ.स.) की कुर्बानी, उनके पैग़ाम और कर्बला की अज़ीम सीखों को याद दिलाने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक सभा साबित हुई।

शारदा नदी में फंसे ग्रामीणों का किया रेस्क्यू, मॉक ड्रिल में परखी बाढ़ से निपटने की तैयारी

पीलीभीत जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कलीनगर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को नगरिया कट क्षेत्र में मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान

सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों, एसएसबी और राहत-बचाव दल ने शारदा नदी में फंसे ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू कर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को परखा। पीलीभीत जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को कलीनगर तहसील क्षेत्र के नगरिया कट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अफसरों ने राहत एवं बचाव तैयारियों का परीक्षण किया। अभ्यास के दौरान शारदा नदी में लोगों के फंसने की काल्पनिक सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया और राहत दल तत्काल मौके पर पहुंच गया। एसएसबी के जवान भी रहे मौजूद मॉक ड्रिल में एडीएम प्रमेश कुमार, नायब तहसीलदार अक्षय यादव, एसएसबी के जवानों व अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। सूचना के अनुसार नदी में कुछ ग्रामीण तेज बहाव के बीच फंस गए थे। इसके बाद राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया। टीम ने नावों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एक प्रशिक्षित गोताखोर ने नदी में छलांग लगाकर डूब रहे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। कुछ लोगों को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया। ग्रामीणों को बताए बाढ़ से बचाव के तरीके - मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने नदी तट पर मौजूद ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। लोगों को चेतावनी मिलने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने, नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और राहत एवं बचाव कार्यों की तत्परता को परखना है।

मौसम का कहर: महोबा में आंधी से बिजली लाइनों में टूटकर गिरे पेड़, 50 गांवों की बिजली गुल, जन-जीवन अस्त-व्यस्त

जैतपुर, अजनर व धवर्रा फीडर से जुड़े गांव की बिजली आपूर्ति पांच घंटे ठप रही। जिससे लोगों

को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोमवार की शाम बूंदाबांदी के बीच तेज आंधी से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। कुलपहाड़-जैतपुर मार्ग पर कई स्थानों पर पेड़ टूटकर बिजली लाइनों में गिर गए। इससे जैतपुर, अजनर और धवर्रा फीडर से जुड़े 50 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई। पांच घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली गुल रहने से मंगलवार की सुबह कई गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही। तेज आंधी में जैतपुर-कुलपहाड़ मार्ग पर 33 केवी बिजली लाइन व टिलवापुरा जैतपुर में हाईटेंशन लाइन पर पेड़ टूटकर गिर गए। इससे तीन फीडरों की आपूर्ति गुल हो गई। इससे जुड़े बेलाताल, लमौरा, अकौना, खमा, अजनर समेत कस्बे के मोहल्लों की आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना पर बिजली निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच पेड़ों की डाल को काटकर अलग लिया। इसके बाद लाइन दुरुस्त करने का काम किया गया। भीषण गर्मी में बिजली गुल रहने से लोग पसीना-पसीना होते रहे।आपूर्ति ठप रहने से कई गांवों की टंकियां नहीं भर सकीं। ग्रामीण दूर-दराज के जलस्रोतों से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर रहे। बिजली निगम के अवर अभियंता गोपाल सिंह का कहना है कि आंधी से बिजली लाइनों में पेड़ गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई।

हाईवे पर रोडवेज बस और पिकअप वाहन की भीषण भिड़ंत, केबिन में फंसा चालक, गंभीर रूप से घायल

बदायूं के बिनावर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बरेली-मथुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया।

गांव भाटपुरी के पास रोडवेज बस और छोटा हाथी वाहन की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में छोटा हाथी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे वाहन से मुश्किल से निकालकर बरेली भेजा गया है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बरेली-मथुरा हाईवे पर गांव भाटपुरी के पास रोडवेज बस और छोटा पिकअप वाहन (छोटा हाथी वाहन) की आमने-सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। हादसे के बाद बस का चालक और परिचालक बस को छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वाहन में फंसे चालक को निकालने का प्रयास किया। केबिन को संबल और सरिया से उठाया, फिर काटा गया। उसके बाद जेसीबी से केबिन खिंचवाकर चालक को बाहर निकाला। चालक की हालत नाजुक है। उसे एंबुलेंस से बरेली भेजा गया। उसके क्लीनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों को भी चोटें आई, लेकिन हादसे के बाद सभी यात्री अन्य वाहनों से अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद लगा जाम - जानकारी के अनुसार छोटी हाथी वाहन बदायूं से बरेली की ओर जा रहा था। जबकि रोडवेज बस बरेली से बदायूं जा रही थी। हादसे में वाहन हरियाणा के यमुनानगर निवासी रनदीप सिंह (32 वर्ष) और क्लीनर हरिपाल घायल हुए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक जाम लगा रहा। बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। पुलिस ने लोगों को किसी तरह से सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे साइड कराया। पुलिस के अनुसार रोडवेज बस पीतल नगरी डिपो की है और बरेली से बदायूं जा रही थी। वाहन बदायूं से बरेली की ओर जा रहा था। हाईवे पर स्थित गांव घटपुरी के पास हादसा हुआ। वाहन चालक के दोनों पैर स्टेयरिंग से नीचे बुरी तरह फंस गए थे। सूचना मिलने पर पहुंची पीआरवी 112 पुलिस और थाना बिनावर पुलिस ने जेसीबी से वाहन का केबिन खिंचवाकर चालक को बाहर निकाला।

सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चे को खोना है... 15 बच्चों की मौत पर बोले अखिलेश- ये बेहद दुखद

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 बच्चों की मौत पर कहा कि अपने बच्चों को खोना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख

परिवारों के दुख की कर सकते हैं बच्चों को खोया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ लेकर बयान दिया की मौत पर कहा को खोना इस है। आप उन कल्पना भी नहीं जिन्होंने अपने है। सपा के अखिलेश यादव अग्निकांड को है। 15 बच्चों कि अपने बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग~ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, कल की घटना बहुत दुखद है। यह दिल तोड़ने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई, और कोचिंग, नौकरी या काम के सिलसिले में वहां गए कई अन्य लोगों की भी मौत हो गई। ऐसी खबरें भी हैं कि बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को फोन कर रहे थे। साथ ही, कई लोग मदद के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। उन परिवारों के दर्द की कल्पना कीजिए जिन्होंने यह नुकसान सहा है। सभी दुखों में, शायद सबसे बड़ा दुख अपने बच्चे को खोना है। किसी भी परिवार के लिए अपने होनहार बच्चे को खोना सबसे गहरा दुख होता है। यह वाकई बहुत दुखद है। वहीं, अग्निकांड पर यूपी के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में बिल्डिंग के मालिक और बिल्डिंग में चल रहे प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और जेल भेजा जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। विवेचना में पुलिस टीम हर पक्ष की जांच कर रही है। तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। विवेचना में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए - 9027776991

संक्षिप्त समाचार

लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई, कटारा कोचिंग सेंटर सहित तीन सील, सात बंद कर भागे

डीआईओएस की जांच टीम कटारा कोचिंग सेंटर पहुंची। कोचिंग

संचालक टीम को संचालन की अनुमति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। न ही उनके पास अग्निशमन विभाग (फायर विभाग) की एनओसी थी। लखनऊ के भीषण अग्निकांड के बाद अलीगढ़ प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीआईओएस की टीम ने क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित कटारा कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। जांच के दौरान कोचिंग संचालक टीम को संचालन की अनुमति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के पास अग्निशमन विभाग (फायर विभाग) की एनओसी भी नहीं मिली। नियमों की अनदेखी और बिना अनुमति कोचिंग संचालन के चलते डीआईओएस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया। साथ ही ग्रेविटी कोचिंग सेंटर, अलीगढ़ कम्पटीशन क्लासेज को भी सील कर दिया गया। सात संचालक कोचिंग सेंटर बंद करके भाग गए।

प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद और नशे में तीन युवकों ने दी जान, अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाएं

सचेंडी, जूही और चकेरी थाना क्षेत्रों में हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों ने जान दे दी। पुलिस की शुरुआती जांच में इन घटनाओं के

पीछे प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद और नशे की स्थिति जैसे कारण सामने आए हैं। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सचेंडी थाना क्षेत्र के भूल गांव निवासी शिवम (19) ने सोमवार देर शाम ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। परिवार में पिता श्यामबाबू, मां बब्ली, भाई करन और बहन पायल है। परिजन ने बताया कि शिवम एक बिस्किट फैक्टरी में काम करता था। कुछ समय से उसका एक युवती से प्रेमप्रसंग चल रहा था और वह शादी करना चाहता था। इसको लेकर परिजन कतई राजी नहीं थे। इस बात को लेकर सोमवार देर शाम वह घर से निकला और घर से कुछ दूरी पर स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, जांच की जा रही है। इसी प्रकार जूही थाना क्षेत्र में कच्ची बस्ती निवासी लोडर इंजन मैकेनिक बृजलाल (55) ने सोमवार रात घर में फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार में पत्नी सुमन, बेटा जितेंद्र है। यशोदा नगर निवासी साढ़ू रामशंकर ने बताया कि बृजलाल सोमवार रात शराब के नशे में घर पहुंचे। इसके बाद सोने मकान के प्रथम तल

हज यात्रा 2027: यात्रा के लिए आवेदन हुए शुरू, 20 जुलाई तक भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म; जमा होंगी इतनी धनराशि

हज-2027 पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके आवेदन 20 जुलाई 2026 की रात 11~59 बजे तक हज कमेटी की वेबसाइट और %%हज सुविधा%% मोबाइल एप के माध्यम

प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ 2026 की रात 11~59 बजे तक हज कमेटी सकेंगे। हज कमेटी की ओर से जारी दिशा-किया जाएगा। अस्थायी रूप से चयनित प्रत्येक करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के बाद हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया से किए जा सकेंगे।हज-2027 पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन इंडिया की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इसके आवेदन 20 जुलाई की वेबसाइट और %%हज सुविधा%% मोबाइल एप के माध्यम से किए जा निर्देशों के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन (कुरआ) हज यात्री को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा किसी प्रकार की छूट या अवधि बढ़ाने का प्रावधान नहीं होगा।उत्तर प्रदेश कि आवेदन के लिए मशीन-पठनीय भारतीय पासपोर्ट (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी हो चुका हो और कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वैध हो), पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो, बैंक पासबुक या निरस्त चेक तथा पते के प्रमाण की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मोबाइल से खींची गई तस्वीरें स्वीकार नहीं की जाएंगीहज कमेटी ने यात्रियों से आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश और घोषणापत्र ध्यान से पढ़ने तथा अपनी पात्रता सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही हज सीट निरस्त करने से बचने की सलाह दी गई है। समिति का कहना है कि सीट रद्द होने से यात्रा व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए हज-2027 की नीति के अनुसार सीट निरस्तीकरण पर निर्धारित दंड भी लगाया जाएगा।लगातार बढ़ रही प्रदेश में हज यात्रियों की संख्या- प्रदेश में हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि वर्ष 2024 में करीब 13 हजार हज यात्री सऊदी अरब गए थे। हज-2025 में करीब 14 हजार से अधिक और 2026 में 18065 हज यात्रियों ने हज किया। वर्ष -2027 के लिए राज्यवार अंतिम कोटा और चयनित यात्रियों की संख्या केंद्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा बाद में जारी की जाएगी।

विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति के उद्देश्यों के प्रति किया गया जागरुक

क्यूँ न लिखूँ सच / भूपेन्द्र तिवारी / पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर गठित मिशन शक्ति टीमों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शासन व पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और मिशन शक्ति के तहत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया। निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी गई मिशन शक्ति 5.0 अभियान के द्वितीय चरण अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी0एम0 स्वानिधि योजना, पी0एम0 सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी0एम0 हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया।

12 साल के दर्श ने गोल्ड पर जमाया कब्जा, बरेली का नाम किया रोशन

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / शूटिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक, कम उम्र में दिखाया बड़ा हुनर बरेली । शहर के 12 वर्षीय होनहार निशानेबाज दर्श कश्यप ने अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बरेली का नाम रोशन किया है। पैसिफिक क्लब, जेल रोड बरेली द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में दर्श कश्यप ने 10 मीटर इंडोर एयर राइफल श्रेणी में बेहतरीन निशाना लगाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दर्श कश्यप, पुलिस आवास जेल रोड बरेली निवासी श्री दीपचन्द्र कश्यप के पुत्र हैं। इतनी कम उम्र में उनकी यह उपलब्धि उनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है। बरेली राइफल क्लब के अनुसार, दर्श अगस्त 2024 से क्लब की शूटिंग रेंज में लगातार अभ्यास कर रहे हैं। नियमित मेहनत और प्रशिक्षण के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। दर्श की इस सफलता पर बरेली राइफल क्लब के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब ने कहा कि दर्श की उपलब्धि शहर के अन्य युवा निशानेबाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

नगर निगम कर्मचारियों का हल्ला - बोल

अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप - माँगा पूरा वेतन

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली । मंगलवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि शासन से मिल रहे वेतन को बड़ी फ़रमे, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर डकार रहे हैं जिससे कर्मचारियों को पूरा वेतन न देकर सिर्फ आधा वेतन 6- 7 हज़ार रुपए दिए जा रहे है ! स्थानीय निकाय सफ़ाई कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित हड़ताल - प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष आशीष वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर सफ़ाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं वहीं भीम आर्मी की ओर से प्रदर्शन में शामिल हुए अतुल वाल्मीकि ने कहा कि कर्मचारियों का आधा वेतन अधिकारी और ठेकेदार मिलकर खाते है और भ्रष्टाचार कर रहे, अब कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दास्त नहीं किया जाएगा यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे ! प्रदर्शन में मुख्य रूप से आशीष कुमार वाल्मीकि , भीम आर्मी के नेता अतुल वाल्मीकि , अमित कुमार , सुपरवाइजर हेमंत कुमार, राहुल राजे आदि पदाधिकारी शामिल रहे ।

बरेली में बड़ी कार्रवाई, दो होटल सील,कोचिंग सेंटरों और मॉल में जांच जारी

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) सतर्क हो गया है। शासन से मिले कड़े निर्देशों के बाद बीडीए की टीम ने अवैध और बिना एनओसी के संचालित होटलों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कड़ी में मंगलवार को बीडीए ने सेटेलाइट बस अड्डा स्थित रजानी होटल को सील कर दिया। यह होटल बिना वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संचालित पाया गया। इसके साथ ही सेटेलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट को भी सील किया गया है। यहां अग्निसुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। बरेली जिला प्रशासन इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सेटेलाइट बस अड्डे जैसे व्यस्त इलाके में स्थित रजानी होटल में बिना एनओसी गतिविधियां चलने की शिकायत पर बीडीए की टीम मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अचानक हुई इस छापेमारी और कार्रवाई से होटल प्रबंधन और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई। बीडीए की टीम ने रजानी होटल और सेटेलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट को सील कर दिया। पुलिस बल मुस्तैद रहा कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद रहा। बीडीए के अधिकारियों ने होटल के सभी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें आवश्यक एनओसी न मिलने पर तत्काल प्रभाव से पूरी इमारत को सील करने की कार्रवाई पूरी की गई।

सीएम योगी के निशाने पर अब लोक निर्माण विभाग, 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट समय सीमा बीतने के बाद भी अधूरे

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे के दौरान पहली बार लोक निर्माण विभाग के कार्यों की अलग से विशेष समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री पेंडिंग कामों का पूरा हिसाब-किताब लेंगे। सीएम का 28 या 29 जून को संभावित दौरा और विभागीय समीक्षा की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी अफसरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पीडब्ल्यूडी के कार्यों का अलग से हिसाब लेंगे । बरेली मंडल में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के ऐसे कई काम हैं, जो तय वक्त के बाद भी अधूरे पड़े हैं। इनमें महत्वपूर्ण भवन निर्माण से लेकर कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के तीखे सवालों और देरी के कारणों का जवाब देना प्रांतीय खंड और निर्माण खंड-वन समेत अन्य शाखाओं के अभियंताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मुकेश चंद शर्मा और प्रमुख सचिव अजय चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान केवल पुराने कामों की ही समीक्षा नहीं होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजी गई करीब करोड़ों रुपये की प्रस्तावित नई कार्ययोजना पर भी गहन मंथन किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा के बाद ही इस भव्य कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। 20 फीसदी से अधिक बिलो टेंडर पर रहेगी नजर- बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में शासन स्तर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि गुणवत्ता प्रभावित होने के डर से 20 परसेंट से अधिक बिलो (कम) दरों पर टेंडर न दिए जाएं। यदि कोई ठेकेदार इससे कम रेट पर काम लेता है, तो उसकी विशेष जांच की जाए। सीएम योगी के सामने होने वाली इस समीक्षा में अभियंता इस बात का भी पूरा ब्योरा रखेंगे कि मंडल में हाल ही में आवंटित हुए टेंडरों में नियमों का पूरी तरह पालन हुआ है या नहीं। चुनावी साल में विधायकों की भी रहेगी नजर चुनावी साल होने की वजह से इस बार लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना पर जनप्रतिनिधियों की भी विशेष नजर टिकी है। सभी विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक सड़कों और विकास कार्यों को इस योजना में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना सकें। हालांकि बैठक के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा कि सीएम कितनी बड़ी सौगात मिलती है।

पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली । नीट की परीक्षा में लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों द्वारा आत्म हत्या के मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

बरेली के रामपुर गार्डन स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंडलीय प्रेस वार्ता कर महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. के. बी. त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि 2018, 2021, 2022, 2024 और 2026 में NEET के पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले 2015 में भी पेपर लीक हो चुका है।

कांग्रेस ने बताया कि 03 मई की परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बड़े पैमाने पर प्रश्न लीक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दबाव में केंद्र सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा।पार्टी ने कहा कि नीट पेपर लीक से पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के विभिन्न राज्यों से अब तक 12 छात्र जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सरकार उत्प्रेरित हत्या मानती है। इनमें राजस्थान के प्रदीप मेघवाल, दिल्ली की अंशिका पाण्डेय, यूपी के रितिक मिश्रा व शिवानी यादव, गोवा के सिद्धार्थ हेगडे, कर्नाटक की भाग्यश्री, एमपी की आकांक्षा चतुर्वेदी, राजस्थान के उमेश माली और रेणु मीणा, उत्तराखण्ड की रिया कुमारी थापा, तमिलनाडु की अनुकीर्तना और गुजरात के कहान पटेल शामिल हैं।

डीएम का बड़ा एक्शन: अस्पतालों की होगी 15 दिन में जांच, मरीजों की सुविधाओं पर मांगे प्रस्ताव

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एसडीएम, सीओ और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाकर 15 दिवसीय अभियान चलाकर अस्पतालों के मानकों की जांच के निर्देश दिए। बैठक में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, मातृ मृत्यु दर, आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई। डीएम ने कमजोर प्रगति वाले क्षेत्रों में सुधार के निर्देश दिए। तीन अर्बन पीएचसी सीबीगंज, मढ़ीनाथ और सुभाषनगर को NQAS सर्टिफिकेट मिलने पर डीएम ने सराहना की और सीएचसी-पीएचसी पर 5 लाख रुपये तक के जरूरी कार्यों के प्रस्ताव मांगे।

डीएम ने बताया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान साफ-सफाई, जलभराव रोकने, एंटी लार्वा छिड़काव, मच्छर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर रहेगा। दस्तक अभियान में आशाएं घर-घर जाकर ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियां भी उपलब्ध कराएंगी, ताकि डायरिया प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मिल सके। बैठक में सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

युवाओं के लिए बड़ा मौका : O-Level और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए मुफ्त आवेदन शुरू, 10 जुलाई तक करें अप्लाई

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली । पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय बरेली की ओर से O-Level और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत O-Level कंप्यूटर प्रशिक्षण एक वर्ष और CCC प्रशिक्षण तीन महीने की अवधि का होगा। प्रशिक्षण के लिए बरेली जिले के चयनित संस्थानों में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कक्ष संख्या-17 बरेली में जमा करनी होंगी।

नशे के सौदागरों पर मीरगंज पुलिस का शिकंजा, अवैध कमाई से खड़ी की गई करोड़ों की संपत्ति पर चला कानून का डंडा

क्यूँ न लिखूँ सच / पं सत्यमशर्मा / बरेली । थाना मीरगंज पुलिस ने स्मैक तस्करी से अर्जित की गई करीब 3 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम गुलड़िया थाना मीरगंज निवासी पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा और उसके पुत्र रोहित शर्मा पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों पर स्मैक तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(2) के तहत संपत्ति फ्रीज कराई है। बताया गया है कि फ्रीज की गई संपत्ति में 4 वाहन और 4 प्लॉट शामिल हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 3.20 करोड़ रुपये से अधिक है। यह संपत्ति आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पंकज उपाध्याय वर्ष 1999 से स्मैक तस्करी के अपराधों में सक्रिय रहा है और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली व मध्य प्रदेश में भी तस्करी से जुड़े मामलों में शामिल रहा है। वहीं उसका पुत्र रोहित शर्मा भी स्मैक तस्करी के मामलों में आरोपी है। मीरगंज पुलिस ने बताया कि कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई। टीम में प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सहित थाना मीरगंज पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

फट गईं नसें और बहता रहा खून: एक्सप्रेसवे हादसे में दरोगा की जिस तरह हुई मौत, कांप जाएगा कलेजा; पीएम रिपोर्ट आई

यमुना एक्सप्रेसवे पर मांट विधायक की सुरक्षा में लगी बोलेरो को हाइवा ने टक्कर मार दी, जिसमें दरोगा राजेंद्र सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण पेट और सीने में चोट लगने से हुई अंदरूनी रक्तस्राव और स्पलीन ब्लीडिंग बताया गया है।मथुरा के मांट विधायक के साथ सुरक्षा में लगे दरोगा की आंतरिक अंगों में रक्त स्राव होने के कारण मौत हुई थी। एक्सप्रेसवे पर जब उनकी बोलेरो हाइवा से टकराई तो उनके पेट और सीने में चोट लगी थी और आंतरिक ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले उनके शरीर के अंदरूनी अंगों से ज्यादा खून बह गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम में उनकी मौत का कारण स्पलीन ब्लीडिंग आया है। विधायक राजेश चौधरी रविवार को अपनी पत्नी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहे थे। वह पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी जा रहे थे और उन्हें दोपहर में एयरपोर्ट से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़नी थी। एयरपोर्ट के पास एक्सप्रेसवे पर मुंबई लिंक इंटरचेंज पर उल्टी दिशा में आ रहे हाइवा ने उनके साथ चल रही एस्कॉर्ट की बोलेरो में सामने से टक्कर मारी थीइसमें उनकी सुरक्षा में लगे दरोगा राजेंद्र सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं अन्य पुलिस कर्मियों के भी चोट आई थीं। हादसे के बाद विधायक ने तत्काल उन्हें अपनी निजी कार से अस्पताल भेजा था, जहां उनकी मौत हो गई थी। दरोगा के बेटे की शिकायत के आधार पर जेवर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने चालक को तत्काल हिरासत में ले लिया था और उसे सोमवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। विधायक ने जताई थी साजिश की आशंका- घटना के बाद विधायक राजेश चौधरी ने अपनी बालाजी की यात्रा स्थगित कर मथुरा लौट गए थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि घटना के पीछे किसी तरह की साजिश भी हो सकती है। पुलिस इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है।ग्रेटर नोएडा डीसीपी रवि शंकर ने बताया कि सारे प्रकरण की जांच पुलिस टीम कर रही है। विधायक की ओर से अभी किसी तरह की लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों और होटलों का होगा व्यापक सेफ्टी ऑडिट, जिलाधिकारी ने गठित की 5 संयुक्त जांच टीमें

क्यूँ न लिखूँ सच /पवन कुमार/ बिना अनुमति संचालित संस्थानों पर होगी कड़ी कार्रवाई, अग्नि सुरक्षा, भवन मानक और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की होगी गहन जांच जनपद में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने सभी कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों एवं होटलों में सुरक्षा मानकों और वैधानिक व्यवस्थाओं की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए तहसीलवार पांच संयुक्त जांच टीमों का गठन किया गया है, जिनमें विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया गया है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित प्रत्येक कोचिंग संस्थान, अस्पताल एवं होटल का सुरक्षा ऑडिट किया जाए तथा भवन सुरक्षा, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा, वैधानिक स्वीकृतियों एवं संचालन संबंधी मानकों की गहन जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, मरीजों एवं आमजन की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान यदि कोई कोचिंग संस्थान या अन्य प्रतिष्ठान निर्धारित अनुमति, मानकों अथवा सुरक्षा व्यवस्थाओं के बिना संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा केवल औपचारिकता न रहकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। जहां भी कमियां पाई जाएं, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने गठित टीमों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाकर विस्तृत सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा चिन्हित कमियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभियान की प्रभावी निगरानी हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

डीएम व एसएसपी नें कछला गंगा घाट का सुरक्षा व्यवस्था,का जायजा

क्यूँ न लिखूँ सच / जिलाधिकारी अवनीश राय व एसएसपी अंकिता शर्मा द्वारा आगामी गंगा दशहरा/ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व के दृष्टिगत थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत कछला बॉर्डर एवं कछला गंगा घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये स्थानों का निरीक्षण कर जायजा लिया गया ।

निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन, पार्किंग व्यवस्था, यातायात संचालन तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंगा घाट पर महिला श्रद्धालुओं की सुविधा,सुरक्षा/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जाये व श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े,सुरक्षित आवागमन,पार्किंग/यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। आगामी गंगा दशहरा/ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस अवसर पर एसडीएम सदर श्री मोहित कुमार,उपनगर आयुक्त श्री विनय मणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी उझानी श्री सुनील कुमार सिंह, क्षेत्रधिकारी यातायात श्री सुनील अहलावत व अन्य अधि0गण मौजूद रहे।

जनता दर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुनी गई जन समस्याएं

क्यूँ न लिखूँ सच / भूपेन्द्र तिवारी / पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों

को सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बध में सम्बन्धित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण जाँच कर निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया । जनसुनवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी उपस्थित रहे।

न्यायिक-प्रशासनिक पारदर्शिता की मिसाल

जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण, बंदियों के अधिकारों व सुविधाओं पर विशेष फोकस

क्यूँ न लिखूँ सच / नीरज कुमार/ न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और मानवीय बनाने के उद्देश्य से जिला कारागार का उच्चस्तरीय संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व विरजेंद्र कुमार सिंह (जिला न्यायाधीश) ने किया। उनके साथ राजेश कुमार पाण्डेय (जिलाधिकारी), विनय कुमार सिंह (पुलिस अधीक्षक), अभिषेक खरे (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), प्रतिभा (सिविल जज-सी.डी./ प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) तथा प्रशांत मौर्य (जेल अधीक्षक) मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार की विभिन्न बैरकों, अस्पताल, पुस्तकालय, रसोईघर, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता तथा सुरक्षा इंतजामों का गहन जायजा लिया। बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार एवं मानकों के पूर्ण अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

कारागार अस्पताल में उपचाराधीन बंदियों की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। चिकित्सकीय सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान बंदियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए उपलब्ध पुस्तकों, अध्ययन सामग्री और पढ़ने की सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया गया, ताकि शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जा सके।

रसोईघर में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों और खाद्य सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव की जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बंदियों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा स्वच्छता में किसी भी स्तर पर शिथिलता न हो।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि कारागार केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। बंदियों के संवैधानिक व मानवाधिकारों की रक्षा के साथ उन्हें सकारात्मक वातावरण देना सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नियमित अनुश्रवण पर जोर दिया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन और निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। यह संयुक्त निरीक्षण कारागार सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल माना जा रहा है।

जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया संयुक्त निरीक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच /पवन कुमार/ बैरकों से लेकर अस्पताल, पुस्तकालय और रसोईघर तक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा, बंदियों के अधिकारों, सुरक्षा एवं सुविधाओं पर विशेष जोर न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला जज विरजेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे तथा सिविल जज (सी.डी.) प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिभा व जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार की विभिन्न बैरकों, अस्पताल, पुस्तकालय, रसोईघर, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तथा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद किया, आवश्यकताओं एवं कारागार में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कारागार अस्पताल में उपचाराधीन बंदियों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने चिकित्सकीय सुविधाओं, दवा उपलब्धता एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था का अवलोकन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुस्तकालय का निरीक्षण कर बंदियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु उपलब्ध पुस्तकों एवं अध्ययन सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई।रसोईघर में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों तथा खाद्य सामग्री के रख-रखाव की भी जांच की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

जिला जज ने कहा कि कारागार केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास का केंद्र भी है। बंदियों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कारागार में विधिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि बंदी समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित हो सकें।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि कारागार में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा बंदियों से संबंधित प्रत्येक व्यवस्था को शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कारागार की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की संभावना को समाप्त करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ रखा जाए।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026: संघर्ष से सफलता तक की कहानी, बिना कोच और संसाधनों के ये खिलाड़ी कर रहे कमाल

मथुरा के जिला स्टेडियम में कई खेलों के नियमित कोच नहीं हैं, फिर भी खिलाड़ी निजी प्रशिक्षण और अपने दम पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। खिलाड़ियों ने खेल विभाग से कोचों की नियुक्ति और संसाधन बढ़ाने की मांग की है।खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों और प्रशिक्षकों के अभाव में जिले के खिलाड़ी संघर्ष के बीच अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। जिला खेल विभाग के स्टेडियम में तैराकी, बैडमिंटन, ताइक्कांडो, तीरंदाजी, वेटलिफ्टिंग, टेनिस और टेबल टेनिस जैसे प्रमुख खेलों के नियमित कोच उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद खिलाड़ी निजी अकादमियों और अपने स्तर पर अभ्यास कर राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले के लिए पदक और ट्रॉफियां जीत रहे हैं।खिलाड़ियों और अभिभावकों का कहना है कि स्टेडियम में खेल सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन प्रशिक्षकों की कमी के कारण प्रतिभाओं को अपेक्षित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। कई खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण के लिए निजी अकादमियों का रुख करने को मजबूर हैं, जहां उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। जिले के कई खिलाड़ियों ने निजी प्रशिक्षण के दम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद खेल प्रेमियों का मानना है कि यदि स्टेडियम में विशेषज्ञ कोचों की नियुक्ति हो जाए तो जिले से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।शुरुआती स्तर पर सही प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन किसी भी खिलाड़ी के करियर की नींव होता है। कोचों की कमी के कारण नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने खेल विभाग से रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां कर खेल सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है, ताकि जिले की उभरती प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सकें और वे प्रदेश व देश के लिए अधिक पदक जीत सकें। जिला क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि स्टेडियम में कोच बढ़ाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। जल्द ही कोच तैनात कर दिए जाएंगे।पंचक सिलेट खिलाड़ी अदिति गौड ने बताया कि स्टेडियम में पंचक सिलेट का कोच न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट कोच से कोचिंग लेने के बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। कुराश खिलाड़ी राधा का कहना है कि स्टेडियम और स्कूल में भी कुराश के कोच नहीं है। परिवार की मदद से निजी कोच से कोचिंग लेने के बाद राष्ट्रीय विद्यालय कुराश प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तीरदांजी खिलाड़ी अरविंद चौधरी ने बताया कि तीरदांजी के कोच स्टेडियम में नहीं है। इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन निजी कोच से सीखने के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में कांस्य एवं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।बॉक्सिंग खिलाड़ी रिषभ गौतम ने कहा कि स्टेडियम में बॉक्सिंग के कोच हैं। अभ्यास भी अच्छा होता है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। अभाव में भी तीन साल में 4 स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।

संक्षिप्त समाचार

बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयो जित किया गया

क्यूँ न लिखूँ सच /पवन कुमार/ कोंच नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने अपने हाथों से कई पेड़ लगाये पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है प्रदीप गुप्ता सबको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए संजीव कुमार तिवारी कोंच(जालौन)। आज श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कोंच रेज सामाजिक वानगी वन प्रभाग उरई के द्वारा कोतवाली की सागर पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता और उनके अनुज समाजसेवी महावीर गुप्ता भी मौजूद रहे इस बलिदान दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के पूर्व क्षेत्रीय वन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी सहित उनकी टीम ने पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया इस कार्यक्रम में चौकी परिसर में वृक्षारोपण किया गया जिसमें पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने अपने कर कमलों से आम आवंला नीम और नींबू आदि प्रजातियों के पेड़ रोपित किये इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि नगर पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि आज के समय में वृक्षारोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हमे शुद्ध ऑक्सजीन की जरूरत है पेड़ लगाने से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है साथ ही पेड़ पौधे हमे हवा छाया देते है उन्होंने आम जन मानस से आग्रह किया है कि अब बरसात के समय में वृक्षारोपण करना चाहिए क्षेत्रीय वन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी ने कहा कि लोगों को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए पेड़ हमारे जीवन के लिये जरूरी है उन्होंने लोगो से ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है इस कार्यक्रम में उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित शर्मा वन दरोगा राजेश अस्थाना वन दरोगा कु0 वर्षा सिंह वन दरोगा शिवम शर्मा वन रक्षक ध्रुव सिंह सहित कई वन विभाग से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

परिवारिक विवाद को समाप्त कराकर 02 परिवारो में सुलह कराते हुए परिवारो को टूटने से बचाया

क्यूँ न लिखूँ सच / भूपेन्द्र तिवारी / आवेदिका द्वारा आपसी पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष सुलह हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर-समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई-झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए खुशी-खुशी साथ रहने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ आपस में सामंजस्य स्थापित कर परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

बदायूं में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार एंबुलेंस ने सात वर्षीय बच्ची को कुचला, मां के सामने मासूम की मौत

बदायूं के कादरचौक चौराहे पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार एंबुलेंस से कुचलकर सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन लेकर फरार हो गयाबदायूं के कादरचौक चौराहे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार एंबुलेंस ने सात वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। एंबुलेंस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। बच्ची की पहचान गोरिया नगला निवासी कोमल के रूप में हुई। कोमल अपने परिजनों के साथ कादरचौक चौराहे पर आई थी। टेंपो से उतरते ही एंबुलेंस की चपेट में आ गई। एंबुलेंस का पहिया बच्ची के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसने मौके पर दम तोड़ दिया। बच्ची दर्द से तड़पती रही थी, लेकिन एंबुलेंस चालक उसे अस्पताल ले जाने के बजाय मौके से फरार हो गया। यदि चालक बच्ची को समय रहते अस्पताल पहुंचा देता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ सुनील कुमार सिंह के अनुसार एंबुलेंस की तलाश की जा रही है। पुलिस सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तड़के हुए सड़क हादसे में युवक की मौत- बदायूं रोड पर सिंह हवेली के पास मंलगवार तड़के करीब तीन बजे सड़क हादसे में बाइक सवार दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बराही निवासी संदीप (19) पुत्र अशर्फी की मौत हुई है।

Gen Z doesn't want to date anyone! Intact relationships are being lost in the world of Reels, study reveals

In this changing world, people are becoming more active on social media and the virtual world rather than being together. The growing trend of Reels is proof of this. Perhaps this is why people are lagging behind in building relationships and the number of unhealthy relationships is increasing. We then start looking for red flags in partners to get out of such relationships. A recent study reveals something similar. In fact, the study found that young people today are afraid to start romantic relationships. Fear of rejection in relationships among Gen Z - A study released by Brigham Young University's Wheatley Institute and the non-profit Institute for Family Studies states that fear and embarrassment regarding relationships is increasing among Gen Z. It's worth noting that this study was conducted among young people aged 22-35 in the United States. Two out of every three men and four out of every five women were reluctant to enter into a romantic relationship. The reason behind this was a lack of confidence. According to the study, a focus on careers, the pursuit of financial stability, the pressures of social media, loneliness, and depression have led the young generation to avoid new relationships because they fear rejection, embarrassment, and emotional vulnerability. Dating and relationships are deteriorating. Experts say that this poor pattern among young people is ruining their lives and relationships. This fear has developed among Gen Z because dating is considered a risk, and they are unaware of the potential mental damage. In other words, the new generation is terrified of breakups and the aftermath. Consequently, Gen Z is protecting itself from these challenges and becoming increasingly self-absorbed. As a result, loneliness is also on the rise. Given the lack of enthusiasm for dating and relationships, this study suggests this is the beginning of a loneliness epidemic.

Amidst the mad rush for fast food, return to your roots and embrace the "farm to plate" principle of yoga.

Through the right ingredients, balanced spices, and conscious cooking techniques, we can make our daily diet yoga-friendly. Through the selection of the right ingredients, balanced spices, and conscious cooking techniques, we can make our daily diet yoga-friendly, easily digestible, and full of vital energy. Learn from Chef Ravikant Pathak's perspective... When we talk about making our diet yoga-friendly, the first and foremost consideration is sattvic food. Sattvic food is pure, natural, easily digestible, and full of positive energy. Incorporating yoga into our kitchen doesn't mean compromising on taste. It truly means creating dishes that don't create heaviness or lethargy in the body. Tamasic and rajasic foods, such as excessive fried food, stale food, or very spicy spices, make the mind restless and the body lethargic. In contrast, sattvic food keeps the body light, which improves concentration and physical flexibility in yoga asanas and meditation. Choosing the right fresh ingredients – To create a yoga-friendly diet, we must embrace the principle of "farm to plate." As a chef, I always recommend choosing seasonal and locally grown vegetables and fruits. Fruits stored in cold storage for months or canned foods containing chemical preservatives do not contain the vibrant prana energy needed for yoga practice. For example, when you incorporate fresh gourds, ridge gourds, pumpkins, green leafy vegetables, and seasonal fruits into your kitchen this season, you are directly absorbing nature's pure energy. Avoiding processed foods, refined sugars, and artificial colors is the most fundamental step on this journey. Furthermore, whole grains like millet, ragi, sorghum, and brown rice are not only a treasure trove of nutrition but also keep the digestive system functioning. The Balance and Importance of Spices - People often have the misconception that sattvic food means tasteless and boiled food. But as a chef, I completely reject this notion. And yes, sattvic food doesn't necessarily mean heavy fasting platters and sweets. In fact, from delicious moong dal khichdi, dal-rice seasoned with asafoetida and cumin seeds, to the exquisite idli-sambar, from Jain cuisine to Marwari cuisine, from prasad to temple food offerings; most foods in Indian cuisine are sattvic, and the spices used in them are a treasure trove of medicinal properties, provided they are used in moderation. A yoga-friendly diet avoids excessive use of spicy spices, garlic, and onion, as these create excessive heat in the body and restlessness in the mind. Instead, we should prioritize digestive and gentle spices. For example, cumin improves digestion, turmeric is known for its anti-inflammatory properties, coriander provides internal cooling to the body, and dried ginger or fresh ginger ignites the digestive fire. Spice combinations should enhance the food's natural flavor rather than overpower it. The secret of cooking: The way and mental state of food is cooked directly impacts its nutritional value. When we combine pure, natural ingredients with proper cooking techniques and positive energy, even a simple meal becomes divine and healthy. Food prepared with a sense of calm, joy, and gratitude is like nectar for the body. For a yoga-friendly diet, cooking should be gentle and minimal. Excessive deep-frying of vegetables or repeatedly heating food over high heat destroys essential vitamins and enzymes, making it difficult to digest. In contrast, steaming, simmering, or cooking covered over low heat are the best yogic cooking techniques. These methods preserve the natural color, texture, and nutrients of vegetables. Ironically, these cooking techniques, stemming from the Indian wisdom tradition, are very popular in Western countries, while we are increasingly turning to fast food and packaged meals. The art of mindful eating—the science of food—is not limited to cooking; the way we consume it is equally important. In yogic science, this is called "mitahara," or mindful eating. A yoga-friendly lifestyle requires complete abstinence from television, mobile phones, or any other mental distractions while eating. When you sit quietly and chew your food carefully, savoring its color, aroma, and true taste, your body releases digestive juices properly. Eating a little less than your hunger and respecting the food on your plate is the true essence of yoga!

Royal Taste, Marwari Style, Step-by-Step Learn to Make Traditional Rajasthani Gatte Ki Sabzi

Gatte Ki Sabzi is a traditional dish from the Marwar region of Rajasthan, which is both delicious and nutritious. Today, we will learn the recipe for Gatte Ki Sabzi, a traditional Rajasthani dish. But first, let's explore its uniqueness and history. Rajasthan is climatically drier than other states, making it extremely difficult to cultivate fresh crops or grow fresh vegetables. Gatte Ki Sabzi became a staple in the local cuisine, requiring no vegetables. Most importantly, this traditional dish is both delicious and nutritious. Let's learn the recipe for Rajasthani Gatte Ki Sabzi: This traditional Rajasthani dish is called Gatte Ki Sabzi, but it doesn't contain any vegetables. Here are the ingredients and method for making it: Ingredients for Gatte: 1 cup gram flour 2-3 tablespoons yogurt 3 tablespoons face cream 1/2 teaspoon celery seeds 1/2 teaspoon fennel seeds 1/2 teaspoon cumin powder 1/2 teaspoon coriander powder 1/2 teaspoon turmeric 1/2 teaspoon ginger paste 1 teaspoon red chili powder 2 teaspoons green chili paste A pinch of baking soda Salt to taste Ingredients for Gravy: 2 tablespoons gram flour 2 cups yogurt 2 tablespoons tomato juice 8-10 curry leaves 3-4 cloves 1/2 teaspoon cumin powder 1/2 teaspoon turmeric 1/2 teaspoon cumin seeds 1 teaspoon red chili powder 3 tablespoons oil Method for making Gatte: Mix all the ingredients and knead the gram flour dough. If you want the Gatte to be a little softer, add more yogurt. Grease your palm with oil. Then, make thin Gatte from the gram flour dough. Pour 3-4 cups of water in a pan and steam the Gatte for 5-7 minutes. Cool them and cut them into small pieces. Method of making gravy: To make the gravy, first mix curd and gram flour. Add a little water and mix well, be careful that there are no lumps in it. After this, mix all the spices including salt and pepper. Now put oil in a pan and fry cumin seeds, cloves and curry leaves. Add the mixture of curd and gram flour. After this, add tomato juice as well. At last, mix the Gatte. Garnish with coriander. Your Gatte ki Sabzi is ready.

A 2-hour, 33-minute film is moving from theaters to OTT platforms within 12 days. The film was leaked online before its release.

A film that premiered at an international film festival is now set to hit the OTT platform. This film only lasted a few days in theaters. The film, which premiered at the international film festival, failed to make a splash at the box office. Within 12 days, the film has moved from the big screen to the OTT platform. This film is none other than "In the Hand of Dante," which premiered out of competition at the 82nd Venice International Film Festival. While the film didn't find a large audience in theaters, social media was eagerly awaiting its OTT release. Now, it's finally known when and on which OTT platform "In the Hand of Dante" will be released. "In the Hand of Dante," a box office flop, premiered at the Venice International Film Festival on September 3, 2025. After nearly nine months, the film was released in theaters. It was released exclusively in US theaters on June 12th. However, the film received a mixed response. Online leaks are being cited as the reason. The film also received a mixed response from critics. Also watch this video: Which OTT platform is the film coming to? - In fact, the film was leaked online even before its release. This is likely why the film suffered a major setback. Due to the lack of audiences in theaters, the film is moving directly from theaters to OTT platforms within 12 days. The film will stream on the OTT platform Netflix from June 24th. What is the story of the film? A handwritten manuscript of Dante Alighieri's poem "The Divine Comedy" is passed from a priest to a mob boss in New York City. There, Nick Tosches verifies its authenticity and takes it for himself.

The film stars Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi and Sabrina Impacchiatore.

This song has been a cult hit for 100 years, with patriotism in every word; the song is in the news because of the singer who was sentenced to 74 lashes.

This song, over 100 years old, is currently in the news. The singer who sang it recently received 74 lashes. A singer was recently sentenced to 74 lashes. The singer was singing a 100-year-old devotional song at a live concert. The video went viral, and the matter escalated to such an extent that she was not only sentenced to lashes but also barred from leaving the country for two years. The reason for this wasn't just her singing, but something else. Which singer was sentenced to 74 lashes? This singer is 29-year-old Parastoo Ahmadi. Iranian singer Parastoo Ahmadi sang a song over 100 years old during a live-streamed performance in December 2024. As soon as the video went viral on social media, the singer and the musicians accompanying her faced increased difficulties. She was taken into custody. However, she was later released. Why was the singer sentenced to lashes? - Now, after a year and a half, an Iranian court sentenced the singer to 74 lashes. She was also barred from leaving Iran for two years and from engaging in artistic activities. She received this punishment because she sang a song in a sleeveless dress without a hijab. She was accused of creating obscene and immoral content online. The song is over 100 years old - Amidst this controversy, there is discussion about the song that Parastoo was singing. This song is now making headlines. It is a patriotic song, composed over 100 years ago. It is called 'Az Khoone Jawanane Watan' (With the Blood of the Youth of the Nation). According to Wikipedia, this song was composed by the famous poet, lyricist, and musician Aref Qazvini and was also the first to perform it. However, its recording is not available online. After Aref, this devotional song was performed by singers such as Iftekhar, Zari and Amjad (1912), and Abdullah Dawami (1914). Several singers subsequently popularized the song in each decade, including Elahe. However, the song gained its greatest popularity in the voice of Mohammad Reza Shajarian, who sang it in 1972. Today, the song has become a cult classic.

Virat Kohli danced to Karan Aujla's "Winning Speech" and revealed why he often listens to it before matches.

Virat Kohli and Karan Aujla had a fun time together at a One8 event in New Delhi, where Aujla sang his hit song "Winning Speech." Virat Kohli and Karan Aujla were seen sharing a great vibe at the spectacular One8 event in New Delhi. The Indian cricket legend shared a stage with the Punjabi singer-rapper, and Karan sang his hit song "Winning Speech" for him. Virat and Karan were seen sharing a light dance and cheering Karan on. Virat Kohli is a fan of Aujla - the moment became even more special when Kohli spoke about his fondness for Aujla and his personal connection with the song "Winning Speech." According to a report in The Indian Express, during an on-stage conversation with the singer, Kohli revealed that he had been a fan of Aujla long before they became friends. He said, "You write songs from the heart, and that reflects. You also tell your own story, which is really special. I like the song 'Winning Speech' the most." Listening to the song brings back memories of his father. Kohli then shared that the song is also very close to his heart and is emotional. Comparing Aujla's journey to his own, Kohli recalled the pain of losing his father at a young age. Kohli added, "It shows the journey he went through, and listening to it reminds me of my own journey. I also lost my father at a very young age. So, this song is very special to me. I often listen to it before going to matches." Virat Kohli reveals future plans. During the evening, Kohli also discussed his ambitions for 'One8 Commune'. Looking to the future, he said he hopes to build the brand into something that transcends his own identity and heritage.